

11 1/21

पत्रावली प्रस्तुत। P.D. साहू के ज कार्ड में स्पष्ट है कि दिनांक 5/2/21 को देस है।

5 2/21

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी एवं वादी-प्रतिवादी ने स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 14.01.21 को न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी संख्या के पहचानकर्ता के तौर पर राजीनामे पर हस्ताक्षर किए।

जरिए राजीनामा पक्षकाराने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रथम पक्षकार (वादी) का चक 24 P प.न. 18/51 (7) कि.न. 1/2, 2 ता 25 कुल 6.198 है. भूमि द्वितीय पक्षकार के कब्जाकाशत की हद तक नाम कलमजब कर द्वितीय पक्षकार के अनुसार वाद डिक्रीकिया जाता है तो प्रथम पक्षकार को एतराज नहीं है एवं द्वितीय पक्षकार का नाम चक 1 PGM प.न. 264/453 (27) कि.न. 1 ता 25 कुल 6.072 हेक्टेयर भूमि में से नाम कलमजब कर प्रथम पक्षकार वाद के अनुतोष के अनुसार प्रथम पक्षकार को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तो द्वितीय पक्षकार को एतराज नहीं है।

हस्तागत वादपत्र, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे एवं रा.का.अ. के प्रासंगिक प्रवधानों का अवलोकन किया गया।

चक 24 P के मु.नं. 7 प.सं. 18/51 की

(अजयकिंद)  
पहचानकर्ता  
(गुलतेजाकिंद)

संजीव कुमार

I 34

Amf

अजयकिंद  
Aev



6.198 है. भूमि वादी के नाम से एवं चक 1 P000V के मु. सं. 27 प. सं. 264/453 की 6.072 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुताबिक राजीनामा पक्षकार चक 24 P के प. न. 18/51 मु. सं. 7 के किला नं. 14 त 25 की कुल 2.986 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को देना चाहते हैं एवं शेष भूमि वादी के नाम से दर्ज करना चाहते हैं।

वादी ने वादें बाबत घोषणा एवं तकसीम प्रस्तुत किया है। अतः के संबंध न्यायालय के प्रेषण निम्नानुसार है -

(i) वादी ने कब्जाकाश के आधार पर घोषणा चाही है, परन्तु राजस्थान कारतकारी अधिनियम में कब्जे के आधार पर घोषणा (अधिकारसी) किस ज्ञाने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल राजीनामे के आधार पर किसी खातेदार कारतकार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजब किया जाना विधिसंगत नहीं है।

(ii) वादी ने तकसीम अर्थात् विभाजन का अनुतोष भी अपने वादपत्र में चाहा है, परन्तु राजस्थान कारतकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत विभाजन का वादपत्र केवल एक सहकारतकार किसी दूसरे/अन्य सहकारतकार के विरुद्ध ही ला सकता है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी उरलग-अलग भूमि के खातेदार कारतकार हैं, न कि किसी संयुक्त खातेदारी भूमि में सहकारतकार। अतः विभाजन संबंधी अनुतोष भी इस वाद में दिया जाना अपेक्षित नहीं है एवं न ही विधिपूर्णा।

(iii) वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को उद्देश्य भूमि का हस्तान्तरण एक-पक्षकार से दूसरे पक्षकार को करना है, जिसका माध्यम केवल विक्रयपत्र, दानपत्र, उपहार पत्र अथवा इकत्यागपत्र इत्यादी ही हो सकता है। अतः राजीनामे के आधार

पर भूमि की हस्तान्तरण की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि पक्षकार भूमि का आदान-प्रदान करना चाहते हैं, तो सक्षम न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष चाराजोई कर सकते हैं।

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं के विवेचन के क्रम में न्यायालय का मत है कि राजीनामे की प्रकृति विधिविरुद्ध होने के कारण यह वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित नहीं है।

— : आदेश : —

फलतः हस्तगत वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा विधिविरुद्ध होने के कारण एवं वादपत्र में चाहा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने के कारण हस्तगत वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत स्टद द्वारा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
5/2/24

(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़